(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाने वाले अपेक्षित नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है ।

(ग) जल (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के उपबन्धों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के उपाय जल प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा तथा जिन राज्यों में केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है, उन राज्यों में यह उपाय राज्य बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1981 तक इन बोर्डों राया चलाए गये मुकदमों तथा दोषसिद्धि के मामलों की संख्या क्रमशः 247 तथा 12 है ।

(घ) जी, नहीं ।

Setting up of fishing Harbour at Neendakara and Vizhinjam

*212. SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Central Government have any proposal to help the Government of Kerala to set up fishing harbour at Neendakara and Vizhinjam;

(b) whether the State Government has submitted any proposal in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) Yes, Sir, the proposals are under examination.

(b) Yes Sir.

(c) Neendakara Fisheries Harbour: This proposal is estimated to cost Rs. 415.36 lakhs comprising Rs. 370 lakhs on harbour and Rs. 45.36 lakhs on shore establishment. It is designed to provide facilities for 1480 mechanised fishing vessels. The main components of the harbour are inner breakwater, wharf, shore facilities and dredging.

Vizhinjam Fisheries Harbour: This project is estimated to cost Rs. 3275.15 lakhs in Stage II, comprising Rs. 700 lakhs on fishing harbour, Rs. 425.15 lakhs on shore establishment and an estimated investment of Rs. 2150 lakhs on fishing vessels. It is designed for deep drought fishing vessels. It consists mainly of breakwater, quay, slip-way, dredging and shore facilities.

Population growth in cities

*213. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether urban congestion has assumed serious proportions and several cities have crossed saturation point and sanitation and drinking water supply have posed serious problems in the cities; and

(b) if so, what measures Government propose to take to check uncontrolled and unplanned metropolitan growth?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Most cities are becoming congested due to inadequate housing, sanitation and water supply.

(b) A centrally sponsored scheme has been introduced for the integrated development of 231 small and medium towns in the country, to reduce the rate of migration to metropolitan and large cities. Besides, projects are in progress in a number of metropolitan cities, for provision of various facilities in the sectors of housing, slum improvement/up-gradation, sewerage, water supply and

traffic improvement with the assistance of World Bank and other international agencies in some of these cities. Action is also being taken to disperse various activities away from the central areas of the cities.

विशाल गंगऊ बान्ध

*214. श्री राम नाथ दुबे : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच प्रस्तावित विशाल गंगऊ बांध के लिए तैयार की गई योजना के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के दबाव के बावजूद विशाल गंगऊ बान्ध के लिए न तो सर्वेक्षण ही किया जा रहा है और न उसका निर्माण आरम्भ किया जा रहा है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार प्रस्तावित योजना के विपरीत गंगऊ बांध के नीचे बने बरियार बांध के बायें किनारे से एक नहर निकाल रही है जिससे उत्तर प्रदेश में केन नदी का पानी नहर में आना बन्द हो जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख), उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने 1-8-1972 और 13-1-1977 के करारों में बृहत्तर गंगऊ बांध को एक संयुक्त कार्य के रूप में प्रारम्भ करने पर सहमति प्रकट की थी, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को सर्वेक्षण, अन्वेषण करने थे और परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी थी । मध्य प्रदेश द्वारा अभी तक परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितम्बर, 1980 में इस बात को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाएँ जाने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया था । मध्य प्रदेश सरकार ने अब सूचित किया है कि सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यों में काफी प्रगति हो चुकी है और परियोजना रिपोर्ट को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

(ग) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 1977 में हुए करार में उत्तर प्रदेश ने वर्तमान बेरियारपुर हेड वर्क्स से एक वाम तट नहर निकालने के मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकार किया था । यह स्कीम भी योजना आयोग द्वारा मार्च, 1978 में स्वीकृत की जा चुकी है और इस समय निर्माणाधीन है ।

Diversion of Imported Edible Oil by Vanaspati Industry

*215. DR. A. U. AZMI:
PROF. AJIT KUMAR MEHTA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Vanaspati Industry siphones the imported adible oils given to it for the manufacture of Vanaspati Ghee at concessional rates so as to produce the ghee at reasonable price, but the same is being used for adulteration into the mustard oil, used by halwais and vendors, bakeries;

(b) whether the imported oil sold through ration shops is finding its way into the blackmarket as it is not popular with the general public;

(c) whether its sale is proposed to be restricted like that of the controlled cloth; and

(d) if so, what steps are envisaged by the Government to cleanse the Administration and implement its policies?